Information in respect of Bombay and Madras is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

दूरदर्शन सीरियल "रामायण"

2148. **श्रीमती रेणुका चौधरी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने "रामायण" सीरियल को 52 भागों के दिखाये जाने के बाद, न दिखाने का निणय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का निर्णय लिए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या 52 भागों में सम्पूर्ण रामायण का दिखाया जाना संभव नहीं है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कहानी रेखा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने प्रारम्भ में अनुमोदित 52 कड़ियों के अतिरिक्त, धारावाहिक में 26 और कड़ियां बढ़ाने का निर्णय लिया है ?

भारत एल्यमिनियम कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता

2149. **श्री शरद यादव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के कर्मचारियों के लिये औद्योगिक मंहगाई भत्ते के आधार पर 1 जनवरी, 1986 को स्वीकृत किये गये अन्तरिम सहायता के भुगतान के निर्णय को भारत अल्यूमिनियम कंपनी लि० (मध्य प्रदेश) के कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी लागू किया गया है ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या भारत एल्यूमिनियम कंपनी के प्रबंधकों ने इस अन्तरिम सहायता के संबंध में सरकार से कोई निर्देश मांगे थे ; यदि हां, तो कब और अन्तरिम सहायता के भुगतान में विलम्ब के क्या कारण हैं और उन्हें इसका कब तक भुगतान किये जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के कमचारियों को 1-1-1986 से अन्तरिम सहायता देय है, जहां मजदूरी समझौते की वैधता-अवधि समाप्त हो गयी है या समाप्त होने वाली है । भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि० (बाल्को) के कोरबा (म० प्र०) के कर्मचारियों की मजदूरी में संशोधन 1-4-1989 को ही देय होगा ।

(ख) बाल्को ने 29-9-1987 को, सरकार से जानना चाहा है कि क्या उन गैर-कार्यपालक कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता दी जाए, जिनका मजदूरी संशोधन 31-3-1989 को समाप्त होने जा रहा है। बाल्को के कोरबा कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने पर सरकार विचार कर रही है ।

उर्वरकों का विक्रय मूल्य

2150. **श्री शरद यादव :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उर्वरकों का प्रति क्विंटल विक्रय मूल्य क्या रहा ;

(ख) इसी अवधि के दौरान उर्वरकों का उत्पादन तथा उपभोग कितना हुआ ;

(ग) क्या 1986-87 में उर्वरकों का उपभोग घट गया है और उर्वरकों का भारी स्टाक बिना बिका पड़ा हुआ है ; और

(घ) क्या किसानों को रासायनिक उर्वरक और खाद सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उर्वरकों के विक्रय मूल्य प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। [देखिए परिशिष्ट CXLIV, अनुपत्र सं० 95]

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में हुए उर्वरकों का उत्पादन तथा उसकी खपत नीचे दी गयी है :—

(एन+पी+के लाख मीटरी टन में)

वर्ष	उत्पादन	खपत
1984–85	51.81	82.11
1985–86	57.56	87.37 (अनुमानित)
1986–87	70.70	87.38

(ग) जी नहीं। 1–10–1987 को लगभग 36 लाख मीटरी टन उर्वरकों के पोषक तत्वों का भंडार बिना बिका पड़ा हुआ था।

(घ) जी नहीं।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी किया जाना

2151. **श्रीमती रेणुका चौधरी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री 6 नवम्बर, 1987 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 7 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों और संघ शासित क्षेत्रों के उपराज्यपालों को आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को कम किये जाने के संबंध में किए गए अनुरोध की बाबत हुई प्रगति का जायजा लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) : आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने तथा उनकी आपूर्ति में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष अगस्त से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उचित दर की 2961 अतिरिक्त दुकानें खोली गई हैं। इसके अलावा, सूखा ग्रस्त राज्यों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए 219 चलती-फिरती वैनें काम कर रही हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने, जैसाकि केन्द्रीय सरकार द्वारा सलाह दी गई थी, आमतौर पर जमाखोरी-विरोधी अभियान को तेज कर दिया है। उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, अगस्त, 1987 से, विभिन्न राज्यों में 31,865 छापे मारे गए हैं, 1198 व्यक्ति गिरफ्तार किये गए हैं, 1297 मुकदमे चलाए गए हैं तथा 11 करोड़ रु० से अधिक मूल्य की वस्तुएं जब्त की गई हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी, केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सलाह के अनुरूप आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तथा उनके मूल्यों की लगातार पुनरीक्षा कर रहे हैं।

Canadian assistance for nylon nets

2152. SHRI K. VASUDEVA PANICKER: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Indian fishery co-operative have received Canadian aid for producing cheaper and better nylon nets; and

(b) if so, what are the details thereof?